(ग) इस सम्बन्ध में अभी तक किये गये उपायों से किसानों को क्या लाभ मिलने की सम्भावना है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) से (ग) विभिन्न फसलों की उत्पादकता में वृद्धि करने के उद्देश्य से सरकार बीज की अधिक फसल देने वाली किस्मों, रसायन उर्वरकों, समय से बुआई तथा पानी का कुशल प्रयोग आदि जैसी नई तकनीकों का प्रचार कर रही है। इससे उत्पादन की प्रति इकाई लागत में कमी होने की आशा की जाती है। वित्त मंत्री जी ने भी 1988-89 के बजट में उर्वरक कम्पनियों द्वारा उर्वरकों की घोषित कीमतों में 7.5% की छूट, कई कीटनाशियों तथा कीटनाशी मध्यस्थों को उत्पाद कर से पूरी छूट तथा सीमा शुल्क में कमी 7500 रु० तक के फसल ऋणों पर ब्याज की दर को 12.5 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने तथा 7500 से 15,000 रु० तक के फल ऋणों पर ब्याज की दर 14 प्रतिशत से घटाकर 11.5 प्रतिशत करने की घोषणा की थी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अधीन पूर्णतया अनुसूचित जाति व जनजातियों के लाभ के लिए धन के आबंटन के प्रतिशत को 10— से बढ़ाकर 20% करके मिलियन कुओं की एक परियोजना प्रारंभ करने का भी प्रस्ताव किया है। इन उपायों से प्रति इकाई लागत कम करने तथा कृषि उत्पादों के लिए ज्यादा लाभ उपलब्ध कराने की आशा की जाती है।

दिल्ली में झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वालों के आर्थिक विकास के लिये धनराशि

2287. **श्री शरद यादव** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा 1987-88 के वर्ष के दौरान दिल्ली में झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वालों के आर्थिक विकास के लिए कितनी धन-राशि आवंटित की गई थी ;

(ख) क्या इस धनराशि को पूरी तरह खर्च कर लिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इस धनराशि को किन शीर्षों के अधीन खर्च किया गया ; और

(घ) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन द्वारा इस राशि का दुरुपयोग किया गया है जिसके परिणाम-स्वरूप सरकार द्वारा नारायणा जैसी अनेक झुग्गी-झोंपड़ी कालोनियो में एक हैंडपम्प तक नहीं लगाया गया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

गांवों का सड़कों से जोड़ा जाना

2288. **श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में अभी भी 65 प्रतिशत ऐसे गांव है जिन्हें सड़कों से जोड़ा जाना है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए राशि का आवंटन पिछली तीन पंचवर्षीय योजनाओं में धीरे-धीरे कम हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा क्या सरकार ने देश में गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर लक्ष्यपूर्ति की कोई तारीख निर्धारित की है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) योजना आयोग के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, देश में बारहमासी सड़कों से अभी जोड़े जाने वाले गांवों की संख्या मार्च, 1988 के अन्त तक लगभग 59 प्रतिशत होने की सम्भावना है।

(ख) ग्रामीण सड़कों का निर्माण मुख्य रूप से राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का भाग है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के लिए परिव्यय पांचवीं पंचवर्षीय योजना (1974–79) में 500 करोड़ रुपये, प्रारूप योजना (1978–83) में 800 करोड़ रुपये तथा छठी पंचवर्षीय योजना (1980 85) में 1164.90 करोड़ रुपये था और सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985–90) में यह 1729.40 करोड़ रुपये है। इस प्रकार परिव्ययों में धीरे-धीरे कोई कमी नहीं हुई है।

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत 1990 तक 1500 से अधिक की जनसंख्या वाले सभी गांवों को और 1000–1500 के बीच की जनसंख्या वाले 50 प्रतिशत गांवों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने की परिकल्पना की गई है।

पड़ोसी राज्यों के शहरों का दिल्ली से जोड़ा जाना

2289. **श्री रशीद मसूद** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में होने वाली और भीड़भाड़ से बचाव की बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पड़ोसी राज्यों के अन्य शहरों को दिल्ली से जोड़ने के लिए विस्तृत योजना तैयार की है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने इस योजना के तहत कुछ क्षेत्रों को आवासीय सीमांकित किया है ;

(ग) यदि हां, तो ये क्षेत्र कहां-कहां स्थित हैं तथा इन क्षेत्रों में आम लोगों द्वारा प्लाट प्राप्त करने के लिए क्या कार्यक्रम तैयार किया है ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि इन आवासीय प्लाटों को गैर-सरकारी निर्माण संस्थाओं को बेचा गया है। यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र–2001 ई० के लिये एक क्षेत्रीय योजना प्रारूप तैयार किया है जिसमें विस्तृत क्षेत्रीय परिवहन नेटवर्क शामिल है।

(ख) क्षेत्रीय योजना प्रारूप में बहुत अधिक भू-उपयोग शामिल हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आयोजना बोर्ड ने सूचित किया है कि भू-उपयोग के ब्यौरे उप-क्षेत्रीय तथा बृहत योजनाओं में दिये जायेंगे।

(ग) और (घ) प्रश्न हीं नहीं उठते।

कृषि एजेंसियों में कीमत निर्धारण पर कार्यदल की सिफारिश

2290. **श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग के सदस्य श्री वाई० के० अलघ की अध्यक्षता में एक कार्यदल गठित किया गया था ;

(ख) क्या यह सच है कि इस कार्यदल ने कृषि के क्षेत्र में मूल्यों के निर्धारण के सम्बंध में अपनी सिफारिशें दे दी हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस कार्य दल ने अपने अध्ययन प्रतिवेदन में यह सिफारिश की है कि किसानों द्वारा प्रयुक्त निवेश मूल्यों में कमी की जानी चाहिए; और

(घ) यदि हां, तो भारत सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या प्रभावी उपाय किये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) से (ग) जी हां।

(घ) 14 राज्यों के चुने गए 169 सम्भाव्य क्षमता वाले जिलों में विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम शुरू किया गया है। विभिन्न संस्थाओं को सहायता प्रदान करके